"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर 17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2003—श्रावण 10, शक 1925

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 2-35/2003/1-8.—श्री एम. डी. दीवान, अवर सचिव, जल संसाधन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उसी हैसियत में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती रेजिना टोप्पो, अवर सचिव, ऊर्जा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उसी हैसियत में जल संसाधन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उसी हैसियत में ऊर्जा विभाग में पदस्थ किया जाता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2003

क्रमांक ई-1-5/2003/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-7-2003 द्वारा श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.से. (1984) संचालक, कृषि एवं पशुपालन, के पद पर पदस्थ किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. श्री दलेई पूर्ववत् सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (सहकारिता), पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर के प्रभार में रहेंगे.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3-7-2003 द्वारा श्री अजयवारा प्रसाद आदिथाला, भा. प्र. से. (एच. पी. 1986) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (सहकारिता) एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पद पर पदस्थ किया गया था एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. श्री आदिथाला पूर्ववत् संचालक, कृषि एवं पशुपालन के प्रभार में रहेंगे.

श्री आदिथाला को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. मिश्र,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2003

क्रमांक 1515/1133/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1350/1133/2003/साप्रवि/1/2लीव, दिनांक 7-6-2003 द्वारा श्री आर. पी. बगाई, प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय रायपुर को दिनांक 27-5-2003 से 7-6-2003 तक (12 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त अवकाश में वृद्धि करते हुए दिनांक 8-6-2003 से 12-6-2003 तक (5 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त आदेश दिनांक 7-6-2003 के बिन्दु क्रमांक 2 से 4 यथावत् रहेंगे.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2003

क्रमांक 1531/1350/2003/साप्रवि/1/2/लीव.—श्री टी. एस. छतवाल, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 14-7-2003 से 26-7-2003 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 12, 13 एवं 27-7-2003 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री छतवाल को अवकाश अवधि में अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

3. श्री छतवाल अवकाश से लौटने पर पुनः सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री छतवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

5. श्री टी. एस. छतवाल की अवकाश अवधि में श्री उजागरसिंह, सचिव, जल संसाधन विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार संभालेंगे

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी,** अवर सचिव.

## श्रम विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जून 2003

क्रमांक एफ11-7/03/16.—छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (सन् 1958 का क्रमांक 25) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित समस्त सॉफ्टवेयर विकास करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी वाणिज्य स्थापनाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा प्रदान करने वाली स्थापनाओं के मॉमले में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 13 के उपबंध लागू नहीं होंगे, परंतु यह कि प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा

Raipur, the 26th June 2003

No. F 11-7/03/16.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 3 of the Chhattisgarh Shops & Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) that State Government shall not apply the provision of section 9 and 13 in the case of all Information Technology commercial establishment engaged in software development and all commercial establishments providing Information Technology Enabled Service (ITES) and which are situated in Chhattisgarh provided, however, that every employee shall be allowd a paid weekly holiday.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2003

क्रमांक F 11-7/03/16.—द्वारा राज्य शासन यह निर्देशित करता है कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा जो नीचे दिये गए अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लेखित है, अनुसूची के कॉलम 3 में दर्शित शर्तों के अनुसार कॉलम 1 में उल्लेखित वर्गों के संस्थानों पर लागू होंगे :—

अनुसूची

| संस्थानों का वर्ग (1) | अधिनियम की धारा (2) | शर्तें (3) |
|---|---|---|
| रेस्टॉरेन्ट एवं भोजनालय जो कि रेलवे स्टेशनों एवं बस स्टैन्डों के 500 मी. की परिधि में है. | धारा 14 (1) | कॉलम 1 में उल्लेखित संस्थानों को रात्रि 2.30 बजे तक खुले रखने की छूट होगी. |

यह अधिसूचना उस तिथि से प्रभावशील होगा जिस तिथि को यह राजपत्र में प्रकाशित होगा एवं यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा.

Raipur, the 16th July 2003

No. F 11-7/03/16.—The State Government of Chhattisgarh by notification No. F 11-7/03/16 directs that the provision of the Shops & Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958), shown in the column 2, of schedule below shall be in force to such classes of establishments mentioned in column 1 of the schedule, subject to the terms and conditions specified in column 3 thereof :—

SCHEDULE

| Classes of establishment (1) | Section of the Act (2) | Terms and condifions (3) |
|---|---|---|
| Restaurants and other eating places within the radius of 500 m. of Raliway stations and Bus stands. | Section 14 (1) | The establishments mentioned in column 1 shall be allowed to function till 2.30 am. |

This exemption shall coe into force, on the day on which it is published in the official gazatte and be operative in the entire State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. एस. मूर्ति, सचिव.**

---

## उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 73-81/2003/उ. शि./38.—छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक विश्वविद्यालय को स्थापित करती है जो ''मोदी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर'' कहलायेगा एवं इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

1. इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) में होगा.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा '' मोदी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, रायपुर'' को ऐसे पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि एवं सम्मान देने की अधिकारिता प्रदान करता है, जिन्हें कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत यदि आवश्यक है, तो विश्वविद्यालय ने मान्यता अथवा अधिकारिता प्राप्त कर ली हो.

Raipur, the 28th July 2003

No. F 73-81/2003/H E/38.—In exercise of the powers conferred in Sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Nizi Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) for extension of Higher/ Technical Education in Chhattisgarh, hereby, establishes a university known as "Modi International University, Raipur" with effect from the date of publication of this notification in the Chhattisgarh Gazette and the jurisdiction of the University shall extend over whole of Chhattisgarh.

1. The Head Office of the University shall be at Raipur (C.G.).

2. The State Government, hereby, authorises "Modi International University" to conduct the syllabus and to grant degree or diplomas for which it shall be recognized or authorised as may be required under any other law for the time being in force.

रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2003

क्रमांक 3357/एफ 73-54/2003/उ. शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत, विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उपनियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है, तथा उपनियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 17 प्रथम संविधियों अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एस. डेहरे, अवर सचिव.

# First Statutes
# of
# MATS University
# Raipur

Established under the Chhattisgarh Niji Kshetra Viswavidyalaya (Sthapna Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002 (No. 2 of 2002)

# STATUTE No.1

Powers of the Chancellor
(Section 14(4) (d) of the Adhiniyam)

The Chancellor shall have the following powers as listed in Section 14(4)(a) to (d) of the Adhiniyam:

1) To call for any information or record
2) To appoint the Vice - Chancellor
3) To remove the Vice - Chancellor

In addition, the Chancellor shall also have following powers:

1) To constitute such committees as he deems necessary to help him in discharge of duties entrusted to him by or under the Adhiniyam.

2) To appoint the Registrar

3) To remove the Registrar

4) To appoint the Chief Finance and Accounts Officer

5) To remove the Chief Finance and Accounts Officer

# STATUTE No.2

Terms and conditions of Appointment of Vice - Chancellor
his powers and duties
(Section 25(1)(b) read with Section 15(1) of the Adhiniyam)

1. The Vice - Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommenced by the Governing Body for a term of four years and shall not be eligible for reappointment for more than two terms.

   Provided that he shall cease to hold the office on attaining the age of 70 years.

   Provided further that not withstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters the office but this period shall not in any case exceed six months

2. The Vice - Chancellor shall be whole time salaried officer of the University. He shall receive salary recommended by University Grants Commission and approved by the State Government from time to time plus other allowances admitted by the Governing body from time to time or as mutually agreed by the Vice - Chancellor and the Trust.

3. During the tenure of office the Vice - Chancellor shall be entitled to have a rent free furnished accommodation maintained by the University.

4. The Vice - Chancellor shall be entitled to use a University vehicle for official purposes. He shall pay such amount for use of the vehicle as may be prescribed by the Government for its vehicles for use by Government officers on monthly basis. The Vice - Chancellor shall also be eligible to use the University vehicle for private purposes and for such journeys he will be liable to pay such charges as are prescribed by Government for private use of Government vehicle by officers on the basis of kilometers involved in priv .e use.

5. The Vice - Chancellor shall be entitled to other benefits such as medical allowance and leave travel concessions as admissible to other University employees.

6. The Vice - Chancellor shall be entitled to traveling allowance from place of his residence on his appointment as Vice - Chancellor and after relinquishment of his charge.

7. The Vice - Chancellor shall have power to constitute such committees as he deems necessary to help him in the discharge of the duties entrusted to him by or under the Adhiniyam.

8. The Vice - Chancellor shall have power to sanction an allowance to any employee of the University for any special duty assigned to such employee for additional duties performed by him which in the opinion of Vice - Chancellor warrants such payment.

   Provided that such allowance shall not exceed 20% of the basic salary of such employee.

   Provided also that the period of such allowances shall not exceed six months.

   Provided further that any action taken under this clause of Statute shall be reported to Board of Management at its next meeting.

9. The Vice - Chancellor shall exercise such other powers as may be given to him / her by the chancellor and the Governing Body from time to time.

10. Subject to the control of the Chancellor and the Governing Body, the Vice - Chancellor shall exercise such financial powers as laid down in the financial regulations approved by the Governing Body.

# STATUTE No.3

Terms and conditions of Appointment of Registrar
his duties and powers
(Section 25(a) read with section 16(1) of the Adhiniyam)

1. The Registrar shall receive salary in the pay scale prescribed by University Grants Commission and admitted by the Governing Body from time to time or as mutually agreed by the Registrar and the Governing Body. He shall draw allowance admitted by Governing Body from time to time.

2. No person shall be eligible for appointment as Registrar unless he/she possesses the minimum qualification as applicable for the post and as determined by the Governing Body from time to time.

3. The Registrar shall be a full time salaried officer of the University.

4. The Registrar shall be entitled to leave, leave salary allowances and other benefits as may be prescribed by the University for its employees.

   The Registrar shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Committee of selection appointed by the Governing Body for a term of 4 years.

   Provided also that he / she shall cease to hold the office on attaining the age of 65 or as prescribed by the Governing Body from time to time.

5. Duties and Powers of the Registrar

   A. Duties-It shall be the duty of the Registrar: -

      i) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University, as the Governing Body shall commit to his charge.

ii) To issue all notice for convening the meetings of the Governing Body, The Board of Management, the Academic Council and other Authorities, Bodies and Committees declared by the Statutes and Authority of the University. He shall act as Secretary of all these Authorities, Bodies and Committees.

iii) To keep minutes of all the meetings of all the Authorities, Bodies and Committees and shall execute the decision taken by them.

iv) To conduct all official correspondence of the University.

v) To arrange for and superintend the examinations of the University.

vi) To send to the Visitor and Chancellor.

a) Copies of the agenda of the meeting of Governing Body, Board of Management and Academic council as soon as such agenda is issued.
b) The minutes of the meeting of the authorities mentioned in 6A(vi)(a) above.
c) Such other papers and information as the Visitor and Chancellor may direct him to supply.

vii) To collect the income, donations etc. and disburse the payment and maintain the accounts of the University through the Chief Finance and Accounts Officer of the University and to see that all moneys are utilized for the purpose they are collected /granted/donated.

viii) To exercise all such powers as may be necessary or expedient to carry out the orders of the Chancellor, Vice - Chancellor and the Governing Body of the University and various authorities, bodies and committees.

ix) To discharge such other functions as may be assigned to him from time to time by the Chancellor, the Governing Body and Vice - Chancellor.

x) To perform such other duties as may from time to time, be entrusted to him by the Statutes, Ordinances, Regulations and Resolutions of Authorities; and

xi) To render such assistance as may be desired by the Chancellor and Vice - Chancellor in the performance of his official duties.

B. Powers of the Registrar

i) Subject to the control of Governing Body the Registrar shall have powers to appoint class III and IV employees of the University and shall exercise disciplinary control over them.

ii) The registrar shall explain the agenda if desired by the Chairman of any Authority, body or Committee, speak at its meeting.

iii) Subject to the control of Governing Body and the Vice - Chancellor the Registrar shall have financial powers including the borrowing of loans for the University and execution of the contracts on behalf of the University.

# STATUTE No.4

Appointment of Deans of the faculty
(Section 12(6) of the Adhiniyam)

1. There shall be a Dean of each faculty in which the University is imparting education.

2. The Dean shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of Vice - Chancellor from amongst the Professors of the University Teaching Department in the subject order of seniority by rotation. Provided that if there is no professor in the University Teaching Department in the subject assigned to the faculty then a Professor of a Centre/Institution teaching the subject may be appointed as Dean in order of seniority by the rotation in the same manner as recommended above. Provided further that if there is no Professor in the University Teaching Department and Centre/ Institution in the subject assigned to the faculty then a Reader of University Teaching Department, Centre/Institution shall be appointed as Dean in order of seniority by rotation.

   Provided also that if no Readers are available, the Chancellor may appoint a Dean of any other Faculty to act as the Dean of Faculty.

3. The term of Dean shall be for a period of two years from the date of appointment.

4. The Dean shall preside over the meeting of faculty and shall give opinion on the recognition of courses as and when referred as the courses of other Universities recognized by the Association of Indian Universities (AIU).

5. The Dean shall perform such other duties as may be assigned to him from time to time by the Board of Management and Academic Council.

# STATUTE No.5

Terms and conditions of Appointment of Chief Finance and Accounts Officer his duties and powers

(Section 25 1(c) read with section 17 (1) of the Adhiniyam)

1. The Chief Finance and Accounts officer shall receive salary in the pay scale prescribed by the State Government for University Finance officer / Deputy registrar plus allowances admitted by the Governing Body from time to time.

2. No person shall be eligible for appointment as Chief Finance and Accounts Officer unless he/she possesses the qualification laid down by the Governing Body for the post from time to time.

3. The Chief Finance and Accounts Officer shall be entitled to leave, leave salary, allowances and other benefits as may be prescribed by the University for its employees.

4. The Chief Finance and Accounts Officer shall be full time salaried officer of the University.

5. The Chief Finance and Accounts Officer shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the Committee of Selection appointed by the Governing Body for a term of 5 year from amongst the applicants responding to the advertisement of the University made for the purpose in All India Daily.

   Provided that the Committee of Selection shall have the power to recommend the name of a suitable person who has not applied.

   Provided also that he/she shall cease to hold the office on attaining the age of 65 or as decided by the Governing Body from time to time.

6. Duties and Powers.

i) Subject to the control of Vice - Chancellor or registrar as the Governing Body may decide it shall be the duty of the Chief Finance and Accounts Officer: -

a) To hold and manage the property and investments of the University including trusts and endowed property.

b) To ensure that the limits to fixed by the Board of Management for recurring and non-recurring expenditure for the year are not exceeded and that all monies are spent for the purpose for which they are granted or allocated.

c) To keep a constant watch on the State of cash and bank balances and on the state of investments.

ii) Subject to the control of the Registrar, the Chief Finance and Accounts Officer shall-

a) Collect the income, disburse the payments and maintain the accounts of the University;

b) Be responsible for the preparation of annual accounts and budget of the University;

c) Have the accounts of the University regularly audited.

d) Ensure that the registers of buildings, land, furniture, equipments, vehicles, etc. are maintained up-to-date and the stock checking is conducted in all offices and institutions maintained by the University.

e) Suggest appropriate action against persons responsible for unauthorized expenditure and for other financial irregularities.

iii) The Chief Finance and Accounts Officer shall have the power to call from any office or institution of the University any information or returns that he may consider necessary for due performance of his duties.

# STATUTE No.6

Other Officers of the University
(Section 12 (6) of the Adhiniyam)

1. In addition to the Officers mentioned in section 12(1) to (5) of the Adhiniyam and other statutes of the University following shall be the officers of the University.

    i) Director
    ii) University Librarian
    iii) Director Physical Education
    iv) Deputy Registrar / Controller of Examination
    v) University Engineer / Estate Officer
    vi) Assistant Registrars

2. The University may have one or more posts of any category mentioned above as per needs and approval by the Governing Body.

3. The Qualifications / Eligibility for each officer shall be in accordance with those prescribed by the UGC / State Government or any other statutory body from time to time.

4. These officers shall be whole time salaried officers of the University.

5. The Officers shall draw salary as recommended by the University Grants Commission.

6. The appointment of the officers shall be made by the Governing Body based on recommendations from committees of selection constituted for the specific purpose of appointing such officers. The registrar shall be the member - secretary of each committee for selection.

7. No person shall be appointed to these posts unless they possess the qualifications laid down for the post by the State Government / UGC and approved by Governing Body.

8. The Governing Body shall appoint a Committee of Selection which shall interview the candidates and prepare a panel of suitable candidates in order of merit.

9. The Governing Body shall make the appointment from the panel given by Committee of Selection.

10. The officer appointed shall execute an agreement and follow the rules and regulations of the University.

11. The officers shall be entitled to the leave, allowances and other benefits prescribed by the University for its employees from time to time.

12. The powers and duties of the officers shall be determined by the Governing Body and incorporated in the second statutes of the university.

# STATUTE No.7

Conditions of service of University Employees
(Section 25 (1)(e) of the Adhiniyam)

Part 1 Definition and Applicability

1. Save as otherwise provided in the Adhiniyam and Statutes the provisions of this Statue shall apply to all the Employees of the University appointed and paid by the University except for those whose services are taken on deputation from Centre/State Government/Body Corporate.

2. In this statute -

   (a) "Pay" means the amount of monthly basic salary of the employees and shall not include any special or additional pay granted to him and any other emoluments which he draws as allowances and largesses.

   (b) "Average pay" means the average monthly pay earned during the ten complete months immediately proceeding the months in which the employee proceeds on leave or is suspended.

   (c) "Vacation post" means a post involving teaching duties when employees are entitled to winter and summer vacations.

Part 2 Classification of post, appointment, terms and conditions.

3) The post in the University shall belong to the class and shall carry the scales of pay as given in appendix.

   (a) The Governing Body shall have the power to appoint the teachers and the officers of the University paid by the University.

   (b) Subject to the control of Vice - Chancellor the Registrar shall have the power to appoint class III., class IV work charge and contingency paid staff of the University.

(c) Save as otherwise provided in Statutes and the Ordinances the qualifications of the post in various categories shall be determined by the Governing Body from time to time.

(d) The channel of promotion and percentages of the post to be filled by promotion shall be prescribed by the Governing Body from time to time. All promotions shall be made on the basis of seniority cum merit and performance appraisals.

4. Temporary appointment may be made to a temporary post or in leave vacancy in respect of permanent post.

5. The whole time University employee shall be at the disposal of University and he may be assigned duties in any manner required by the proper authority without claim of Additional remuneration.

6. The Board of Management may permit a University employee to perform a specified service for a private person body or Government and to receive remuneration thereof in form of fee, if it is satisfied that this can be done without detriment of his official duties or responsibilities.

Provided that half the amount of fees so received shall be credited to fund of the University.

1. The Head of the Branch, Department, Institute under whom the employee is working shall send to Registrar in form prescribed by the University, a confidential report, every year not later than 30th April, on the work and conduct of the employee during the preceding year ending on 31st March.

2. The confidential report and the opinion stating the employee fitness or otherwise for confirmation in service must be sent to the Registrar by the head of Branch or Department or Institute, where the probationer is working at least one month before the date of expiry of the probation.

3. A temporary appointment may be terminated by either party without assigning any reason by giving to the other one month's notice or one month's salary in lieu thereof. No such notice of payment of salary shall

be necessary in case of termination of service or work charge or contingency paid employee.

4. (a) If the appointing authority is not satisfied that with and /or conduct of the employee on probation his services may be terminated. In case of termination of the service of the employee on probation, one month's notice shall be given to him or in lieu of notice, he will be paid one months salary. The probationer may also terminate the engagement by giving one month's notice or one month's salary.

   (b) If the probationer was appointed by promotion and his work and conduct is not satisfactory the appointing authority may revert him to the post held by him before such promotion and such reversion shall not be deemed to be a penalty.

   (c) Every person appointed to permanent post under University by promotion or direct recruitment shall on satisfactory completion of his period of probation shall be eligible for confirmation in the post.

5. On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on the post. A University employee holding a permanent post substantively, if appointed substantively to another post acquires a lien on second post and ceases to hold any lien on the first one.

6. A permanent employee shall be required to give 3 months notice in case he wishes to resign or he shall pay to University 3 months salary in lieu of such notice. If the University terminates the services of a permanent employee a notice to that effect shall be served on him, 3 months before the date on which he is to be relieved. In the absence of such notice the University shall pay him 3 months salary. Such notice shall not be necessary if the employee is removed from the service, dismissed or compulsorily retired.

7. Before leaving the University service an employee, whether appointed temporarily or on probation or permanently shall hand over the charge of his post to the employee duly authorized to receive charge and shall return to the University all articles entrusted to him for his use and clear all dues outstanding against him.

8. University employee shall be entitled to leave as per the leave rules framed by Board of Management and approved by the Governing Body.

Part 3- Suspension, Penalty and Disciplinary Authority:

9. (1) The appointing authority may by an order place an employee, under suspension

(a) When disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending

Or

(b) On confirmation of a prime facie case against an employee on the charges of financial irregularities and / or unethical activities detrimental to the interest of the University.

Or

(c) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority

(a) With effect from the date of his detention, if in the detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours.

(b) With effect form the date of his conviction, if he is event of a conviction for an offence, he is sentenced to imprisonment and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

(3) An order of suspension made or deemed to have been made shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the appointing authority.

10. The services of a university employee may be terminated on any of the following grounds
   (a) Willful neglect of duty
   (b) Misconduct / indiscipline
   (c) Physical and mental unfitness
   (d) On the abolition of post held by him
   (e) Conviction by a court of law for an offence involving moral turpitude.

11. (1) The appointing authority may for good and sufficient reasons, impose on an employee the following penalties.

   (a) Censure
   (b) Recovery from his pay, whole or part of any pecuniary loss caused to the university by negligence or breach of order by the employee.
   (c) With holding the increments of pay.
   (d) Reduction to lower time scale of pay, grade or post.
   (e) Compulsory retirement.
   (f) Removal from service
   (g) Dismissal from service.

Besides the above penalties, reasonable fine may be imposed on class IV employee for petty carelessness, unpunctuality etc.

(2) The appointing authority may institute the disciplinary proceeding against the employee in accordance with the procedure laid down by the Governing body.

12. Where the penalty is imposed by the Registrar the employee may prefer an appeal to Vice - Chancellor within thirty days from the date on which order is served on the employee.

Part 4- Miscellaneous

13. Every employee shall at all times:
   (a) Maintain absolute integrity
   (b) Show devotion to duty; and
   (c) Do nothing which is unbecoming of an employee of the University.

14.No employee shall join or continue to be member of such association the objects and activities of which are prejudicial to the interest of the University or public order, decency or morality.

15.No employee shall-

i) Participate in Public protests / Dharana / Hartal / demonstration prejudicial to the interest of University

ii) Resort to any violence

iii) Participate in editing, management of any print or electronics media without prior sanction of the University.

iv) Divulge in any matter of the University any where other than the competent authority.

v) Take any employment elsewhere either full time or part time without prior sanction from the University.

16.Any infringement of para 15, (1) to (5) of this Statute shall be regard as subversive of good discipline and misconduct and will justify the initiation of disciplinary action against such employee.

17.The employees shall have a contributory provident fund as prescribed in the contributory provident fund act as amended from time to time.

18. The scales of pay of different categories of employees shall be such as may be prescribed by the UGC and approved by the State Government applicable to the employees of the University established by the State Government.

## STATUTE No.8

Arbitration to resolve Disputes

(Section 25(1) (f) of the Adhiniyam)

1. In the event of dispute arising between the employee and the employer, on the request of the employee the Vice - Chancellor shall appoint an Arbitrator not below the rank of District and Session-Judge who shall listen to both the parties and pronounce his award.

2. The Board of Management shall consider the award and act as per directions of the Arbitrator to resolve the Dispute.

3. If either of the parties i.e. employee or the employer is not satisfied with the award they can approach the Chancellor to appoint a tribunal.

4. The tribunal shall consist of following members

   i) A nominee of the Chancellor not connected with the university who will act as the Chairman.
   ii) The nominee of the aggrieved employee and
   iii) A nominee of the Board of Management

   Provided that the aggrieved party shall approach the Chancellor within 30days of the receipt of the award.

5. The decision taken by the tribunal shall be binding on both the parties.

6. The disputes regarding constitutions of authorities / bodies or nomination of any member in the authorities / bodies provided for by or under the act/statute/ordinance shall be decided by the Chancellor in the manner he deems fit and his decision shall be final.

# STATUTE No.9

Honorary Degree
(Section 25(1) (g) of the Adhiniyam)

1. A proposal for conferment of Honorary degree shall be made by Academic Council.

2. The proposal shall be placed before a Committee consisting of the Vice - Chancellor , one eminent educationist not connected with the University and one educationist nominated by the Visitor.

3. If the Committee unanimously recommends that a honorary degree be conferred on the person on the ground that he is in its opinion a fit and a proper person to receive such degree, its recommendation shall be placed before Governing Body and the report of which shall be sent to the Visitor.

4. The honorary degree shall be conferred on the person either at a regular convocation as prescribed in the regulations to be made by the Board of Management or at a special convocation to be held for the purpose as may be decided by the Governing Body.

# STATUTE No.10

Exemption from tuition fee and Award of Scholarship
(Section 25(1) (h) of the Adhiniyam)

1. The assistance obtained from the Central Government, State Government or any other authority, funding agency etc. towards meeting full or in part any amount towards fee otherwise payable by students belonging to socially disadvantaged or economically weaker sections shall be disbursed strictly as per directions of the authorities providing such assistance.

2. It shall be the duty of the Registrar and the Chief Finance and Accounts Officer of the University to ensure that the students get the stipend exactly as per the directions of the funding agency.

3. The University will also make provisions for the award of fellowships, scholarships and stipends from its own sources. The terms and conditions of the award shall be laid down in the ordinance made under section 27 (1) (d) of the Adhiniyam.

# STATUTE No.11

Policy of Admission including Reservation of seats
(Section 25(1) (i) of the Adhiniyam)

1. The admission to various courses shall be made exactly in order of merit made on the basis of the marks obtained at the qualifying examination.

   Provided that in the courses the University decides to admit the students on the basis of the entrance test held either by the University or by any body / agency on behalf of the University the admission shall be granted on the basis of merit secured at the entrance examination.

2. The reservation of seats at each institution/center in each course of study shall be as per rules framed for the reservation of seats for SC/ST/OBC and other categories by the Government of Chhattisgarh from time to time and applicable on the University.

## STATUTE No.12

Provisions Regarding Fee to be charged from the students
(Section 25(1) (j) of the Adhiniyam)

1. The fee for each course of study, as determined by the Governing Body, shall be incorporated in the second statutes of the University with all attendant details.

# STATUTE No.13

Provisions Regarding Number of Seats in Each Course
(Section 25(1) (k) of the Adhiniyam)

1. In each post graduate course the maximum number of students admitted shall be 30 per section at the University teaching department and its different centers. The University shall, however, decide the number of students to be admitted at a center on evaluating its infrastructure facilities and strength of faculties. In no case the number shall exceed 30 per section for a particular course at a particular center.

2. At the graduate degree level each section of the class shall have a maximum strength of 60 students.

   The number of sections which can be allowed at a particular center shall be adjudged on the basis of the infrastructural facilities available at the center and the faculty strength.

3. The Academic Council shall lay down the norms having details regarding the infrastructural facilities and required strength for each course and place it before the Board of Management on being approved by it, it shall be strictly followed for deciding the seats in each course at each center.

# STATUTE No.14

Academic Council
(Section 19(1) (3) of the Adhiniyam)

1. (a) The Academic Council shall consist of following members:

i) Vice - Chancellor - Chairman

ii) Deans of faculties of the Universities

iii) Chairman Board of Studies

iv) Professors of the University

v) Five teachers of centers nominated by the Vice - Chancellor in rotation by seniority.

vi) Two lecturers of the University nominated by the Vice - Chancellor in rotation by seniority.

vii) Registrar - Secretary

(b) One third of total members of Academic Council shall form the quorum.

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meetings.

(c) The academic council shall have the power to co-opt as members persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the council for consideration. The member so coopted shall have all the rights of the members of the council.

(d) All the members of the Academic Council other than ex-officio members and members referred in sub-para (c) shall hold the office for a term of three years.

2. The Academic Council shall have following powers and perform following duties.

i) To exercise general supervision over the academic policies of the University and to provide directions for methods of instructions, cooperative teaching for the improvement of academic standards.

(ii) To consider matters of general academic interest and to take appropriate action in this regard.

(iii) To assign departments to the faculties and to nominate its own members to the faculties.

(iv) To make proposals for the institutions of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes and to make rules for their award.

(v) To consider the proposals for granting affiliations for the colleges of the University and for establishment of University Study Centers/University Teaching Centers as prescribed in the act and statute.

(vi) To prescribe qualifications for recognition of persons as teachers of the University and to accord such recognition.

(vii) To make arrangements for the conduct of examination and arrange for the publication of the results.

(viii) To prescribe the qualifications for the award of certificates, Diplomas and Degree.

(ix) To recognize eminent persons of any subject as Honorary Professor and to guide research in that subject.

3. The Academic Council may appoint a standing Committee consisting of:

(i) Vice - Chancellor - Chairman
(ii) 3 Deans of faculties in order of seniority by rotation to be nominated by the Chancellor
(iii) Registrar - Secretary

4. The "Standing Committee" shall have following powers and shall perform following duties

(i) The meeting of the Committee shall be convened under the direction of Vice- Chancellor

(ii) It shall render advice on the equivalence of examinations in consultation with the faculty, concerned.

(iii) It can dispose off any matter of academic council and report it at the next meeting of Academic Council.

(iv) Standing Committee may invite such persons who can render fruitful advice the matter under consideration.

# STATUTE No. 15

## Conduct of Examinations
(Section 27 (1) (E) of the Adhiniyam)

1. The conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators shall be governed by the provisions of the ordinances of the University.

## STATUTE No. 16

Establishment of Study Centers of the University
(Section 3 (7) of the Adhiniyam)

1. The University shall establish University Study Center as defined in Section 3(7) of the Adhiniyam.

2. The University Study Center shall be established by the Board of Management on the recommendation of a inspection committee to be appointed by the Board of Management consisting of experts in the subject for the courses run by the University.

3. The University Study Center shall have academic infrastructure, laboratory, library, teaching staff and all such other facilities may be required for imparting education in the course of studies/subjects concerned.

4. The University Study Center shall collect the fee from each student for the course of studies for which the student is registered with the University from time to time.

5. The Examination of the candidates studying at the University Study Center shall be held under the supervision of the university and at centres to be specified in the subsequent statutes of the University.

# STATUTE No. 17

Admission of College to the privilege of the University /Affiliation
(Section 6 (2) of the Adhiniyam)

1. The University may admit/affiliate colleges to the privileges of the University on the recommendation of the Academic Council.

2. The affiliation will be granted by the Board of Management to such Institutions/Colleges which are providing regular course of studies for the courses in the faculties of the University with due permission of the State Government of Chhattisgarh and prior permission of such other statutory bodies of which permission is required to run such courses of studies viz.. AICTE, NCTE, INC, MCI, DCI, PCI and ICAFRA etc.

3. The Institutions / Colleges shall be granted affiliation only after an inspection by a committee appointed by the University.

4. The Institutions / Affiliated Colleges shall have .staff laboratory and the facilities as are required for running the course of studies and shall abide by the conditions as may be laid down the Board of Management from time to time.

5. The teachers of the affiliated Institutions/Colleges shall have the same qualification and pay scale prescribed by the UGC and as is applicable to the Government Colleges and as may be approved from time to time by Board of Management of the University.

6. The affiliated colleges shall follow the code laid down by the Board of management of the University.

7. The institutions/Colleges for the Ist year for 3/5 (3+2) years degree course or for Ist year (previous) of a P.G. course as temporary affiliation and the college shall be required to apply a fresh for affiliation to II year and III year for the course of study as the course may require.

8. The Institutions/Colleges affiliated to the University shall abide by the "College Code" which may be prescribed by a Statute to be framed by the Board of Management and Governing Body.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2003

क्रमांक एफ 73-105/उ. शि./2003/38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत दि आई. सी. एफ. ए. आई., युनिवर्सिटी, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत, विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों की उपनियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है, तथा उपनियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 25 प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सी. एस. डेहरे**, अवर सचिव.

# THE ICFAI UNIVERSITY

15 Jalashay Marg,
Chowbey Colony,
RAIPUR, Chattisgarh

## FIRST STATUTES

# The ICFAI University

Established under section 5 of the Chattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002, vide Notification of the Government of Chattisgarh, No. F-73/105/HE/02 dated 27th September 2002.

## FIRST STATUTES

Made in accordance with the provisions section 25 of the Chattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002

**1 Short Title, Extent and Commencement**

a. These Statutes shall, here-in-after called, 'the The **FIRST STATUTES of the ICFAI UNIVERSITY, 2002.**

b. The First Statutes are applicable to **'the ICFAI University,'** and any matter relating to or and incidental thereto.

c. The First Statutes shall come into force on the date of publication of the First Statutes by the Government of Chattisgarh in the Official Gazzette.

d. The Registered office of the ICFAI University shall be situated at Raipur.

**2 Definitions**

In these First Statutes, unless and otherwise the context demands:

a. Act means, the Chattisgarh Niji Kshetra Viswa Vidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam 2002.

b. **Academic Year** means the period from June 1of any year to May 31 of the following year;

c. **Ad-hoc committee** means a committee constituted under the Section 17.0 of these First Statutes.

d. **Affiliation** means and includes recognition of colleges, association of colleges located in or outside Chattisgarh, and admission of such colleges under the University for the purpose of conducting the educational and professional programs of the University.

e. **Authorities mean** authorities mentioned under Section 19 of the Act, Section 11 of these First Statutes.

f. **Academic Council** means the Academic Council constituted under section 22 of the Act and under Section 14.0 of these First Statutes.

g. **Board** means the Board of Management of the University constituted under Section 21of the Act and Section 13.0 of these First Statutes.

h. **Chancellor** means the Chancellor of the University as mentioned in section 14 of the Act and Section 7.0 of these First Statutes.

i. **Committee** means all committees constituted under Sections 15,16,17and 18 of these First Statutes.

j. **Common Seal** means the authoritative seal of the University established under section 6 of the Act.

k. **Course** includes programs and courses of studies imparted in the classroom framework and also in the distance mode;

l. **Distance education** includes the education / courses / programs provided to students on off campus mode.

m. **Fund** means the fund established under Section 7 of the Act and Section 20.0 of these First Statutes.

n. **Financial year** means the period commencing on the 1st April of any year and ending with 31st March of the following year;

o. **Finance Committee** means the Finance Committee constituted under Section 23 of the Act and Section 15.0 of these First Statutes.

p. **Government** means the Government of the State of Chattisgarh.

q. He includes She and His includes Her;

r. **Institute** means any institute constituted as part of the University to deal in different disciplines, located within or outside the state of Chattisgarh.

s. **Manual of Instructions** includes all rules, procedures, instructions and systems laid down by various committees, Boards, authorities, officers of the University for the purpose of smoothly conducting the business of the University.

t. **Ordinance** means ordinance issued by the University as prescribed by Section 27 of the Act.

u. **Rules** mean the Rules made under Section 36 of the Act.

v. **Regulations** mean Regulations made under Section 37 of the Act.

w. **States** means the States of India formulated under the relevant legislation of the Parliament.

x. **Statutes:** Means the Statutes made under Section 25 and 26 of the Act and includes the amendments, alterations and modifications of the Statutes.

*y.* **Sponsor** means the ICFAI Society registered at Raipur, Chattisgarh under the provisions of Chattisgarh Panjikaran Adhiniyam.

*z.* **Student** means a student of the University and includes any person who is enrolled to pursue any course of study at the University;

*aa.* **Staff** means the teaching and non-teaching employees of the University who are on direct permanent payroll of the University and does not include any casual, temporary, contractual, ad-hoc employees or visiting persons who may be engaged for a specific assignment or task;

*bb.* **University** means the ICFAI University established under section 5 of the Act and will have the same meaning as stated in the University Grants Commission Act, 1956;

*cc.* **Vice-chancellor** means the Vice-chancellor of the University appointed within the meaning of section 15 of the Act and Section 8.0 of these First Statutes.

*dd.* **Visitor** means the Visitor as defined under section 13 of the Act and Section 6.0 of these First Statutes.

**3.0 Objects of the University**

The main objects of the University are as follows:

a. To provide instruction, teaching and training in the field of higher education; and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge;

b. To establish a campus in the State of Chhattisgarh and to have affiliate institutions and study centers at different places in India and other countries;

c. To create higher levels of intellectual abilities;

d. To establish state of the art facilities for education, training and research;

e. To offer continuing and distance education programs;

f. To institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examination, or any other method of evaluation;

g. To ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions are of high standard.

h. To encourage and promote research activities and set up independent research institutions for pure and applied research, and institute awards and fellowships at institutions other than the University for undertaking research.

i. To affiliate or collaborate with any other college or university, research institution, industry, association, professional association or any other organization, in India or overseas, to conceptualize, design and develop specific educational and research programs,

training programs and exchange programs for students, faculty members and others.

j. To undertake surveys, studies and consultancy for any organization in India or overseas.

k. To disseminate knowledge through seminars, conferences, executive education programs, community development programs, publications, and training programs.

l. To undertake programs for the training and development of faculty members of the University and other institutions in India or overseas.

m. To undertake collaborative research with any organization in India or overseas, and undertake commercialization of technologies.

n. To develop, register and licence all forms of Intellectual property rights, including, interalia, trademarks, copyrights, know-how and patents, etc.

o. To conceptualize, design, develop and commercialize various products, equipment and machinery as part of the research and development activity.

p. To encourage sports, cultural, and extra curricular and co-curricular activities for students and staff.

q. To do all things necessary or expedient to promote the above objectives.

r. To pursue any other objective as may be approved by the Board.

**4.0 Appointment and powers of the Chancellor.**

a The Chancellor shall be appointed by the Sponsor with the prior approval of the Visitor.

b The term of office of the Chancellor shall be three years, and he may be reappointed for successive terms, at the pleasure of the Sponsor.

c The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and the head of the University.

d The Chancellor shall preside over the Convocation of the University, when the Visitor is not present.

e The Chancellor shall have the following powers:

- i To call for any information on record.
- ii To appoint the Vice-chancellor.
- iii To remove the Vice-chancellor.
- iv Such other powers as may be delegated to him by the Governing Body.

f. If in the opinion of the Sponsor, the actions of the Chancellor are found to be in any way detrimental to the interests of the University, the Sponsor shall appoint such other person as may be found appropriate in the position of Chancellor to succeed the person so acting. Provided that, the Sponsor shall seek the prior approval of the Visitor before appointing such other person as the Chancellor. The Sponsor may stipulate the date from which such other person shall assume the office of the Chancellor.

g. The General Body may from time to time decide on the Honorarium and / or the pay and / or allowances to be paid to the Chancellor and / or perquisites to be provided to the Chancellor.

h. The office of the Chancellor may be located anywhere in India or overseas.

**5.0 Appointment, powers and responsibilities of the Vice-Chancellor.**

a. The Vice-chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three persons recommended by the Governing Body.

b. The term of office of the Vice-chancellor shall initially be Four years, and he may be reappointed for successive term(s) by the Chancellor.

c The Vice-chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and also the ex-officio member of the Governing Body, Board of Management, Academic Council, and other Committees that may be set up by the Governing Body or the Board from time to time.

d The Vice Chancellor shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall execute the decisions of the various authorities of the University; and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Act and the Statutes.

e In absence of the Chancellor, the Vice-chancellor shall undertake all the functions of the Chancellor, and shall preside over the Convocation in the absence of the Chancellor.

f If in the opinion of the Vice-chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under the Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

*Provided that if in the opinion of the concerned authority such action should not have been taken by the Vice-chancellor then such case shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.*

*Provided further that where any such action taken by the Vice-chancellor affects any person in the service of the University such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Board of Management and the Board of Management may confirm or modify or reverse the action taken by the Vice-chancellor.*

g. If in the opinion of the Vice-chancellor any decision of any authority of the University is outside the powers conferred by the Act, Statutes or Ordinances or is likely to be prejudicial to the interests of the University, he shall request the concerned authority to revise its decision within

seven days from the date of his decision and in case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within seven days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final.

h. If at any time upon representation being made or otherwise, and after making such enquiries as may be deemed necessary, the Chancellor by an order in writing stating the reasons therein, may ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.

**6.0 Appointment, powers and responsibilities of the of the Registrar**

a The Registrar shall be appointed by the Vice-Chancellor, based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose, with the approval of the Chancellor.

b The selection committee shall consist of the following members:

- i. One representative of the Chancellor.
- ii. One representative of the Sponsor who is also a member of the Governing Body
- iii. One expert nominated by the Board of Management, who is not in any way connected with the University.

c. The term of office of the Registrar shall be as mentioned in the order of his appointment by the Vice-Chancellor.

d. The Registrar shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

e. The Registrar shall draw such emoluments, which shall not be less than the emoluments of Professor or equivalent person as prescribed by the UGC from time to time.

f. The Registrar shall undertake such functions as may be specified by the Governing Body or the Board of Management or the Vice-Chancellor.

g. The Registrar shall be the ex-officio Secretary of the Board of Management, the Academic Council and such other authorities and bodies as may be constituted by or under the Act or the Statutes or the Ordinances.

h. The Registrar shall report to the Vice-Chancellor.

i. The following shall be the duties of the Registrar:

- i. To be the custodian of the records, common seal and such other property of the University as the Governing Body or the Board, shall commit to his charge;
- ii. To conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the University.

iii. To collect all income and disburse the same for the purposes of the University as sanctioned by the Vice Chancellor.

iv. To make Agenda and issue Notices of meetings of the authorities of the University and all committees and sub-committees appointed by any of these authorities with the approval of the Vice Chancellor.

v. To keep the minutes of the meetings of all the authorities of the University and of all the committees and sub-committees appointed by any of these authorities and circulate the same among the members, with the approval of the Vice Chancellor.

vi. To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and perform pleadings or depute his representatives for this purpose.

vii. To enter into agreements, contracts on behalf of the University and make amendments and alterations in the terms of such agreements or contracts as may be directed by the Board.

viii. To sign documents and authenticate records on behalf of the University.

ix. To submit information, reports and documents to the Government and conduct liaison with the Sate Government, Central Government, University Grants Commission and other Government authorities.

x. To generally supervise the administration function at the University.

xi. To supervise and manage the conduct of the Examinations of the University, subject to control of the Vice Chancellor.

xii. To perform such other duties as may be as may be specified by the Board of Management or the Vice-Chancellor from time to time.

**7.0 Appointment, powers and responsibilities of the Chief Finance & Accounts Officer.**

a The Chief Finance & Accounts Officer shall be appointed by the Vice-Chancellor based on the recommendation of the Selection Committee appointed for the purpose.

b The selection committee shall consist of:

i. The Registrar

ii. One representative of the Chancellor.

iii. One representative of the Sponsor who is also a member of the Governing Body

iv. One expert nominated by the Board of Management, who is not in any way connected with the University.

c The Chief Finance & Accounts Officer shall have such qualifications and experience as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

d The Chief Finance & Accounts Officer shall draw such salary, allowances and entitled such perquisites which shall not be less than the emoluments of the Deputy Registrar or equivalent person as prescribed by the UGC from time to time.

e. The term of office and the terms of appointment of the Chief Finance Officer shall be as mentioned in his order of appointment by the Vice-Chancellor.

f. The Vice-chancellor may appoint a person to officiate as the Chief Finance officer, in the event of temporary absence of the Chief Finance and Accounts Officer.

g. The Chief Finance & Accounts Officer shall exercise general supervision over the funds of the University and shall have such powers and responsibilities as may be delegated or assigned to him by the Board of Management or the Finance Committee or the Vice-Chancellor or the Registrar.

h. The Chief Finance & Accounts Officer shall report to the Registrar.

**8.0 The Governing Body**

The Governing Body shall be the supreme authority of the University.

**8.1 Constitution of the Governing Body**

The Governing Body shall consist of the following members:

(i) The Chancellor

(ii) The Vice-chancellor

(iii) Three persons nominated by the Sponsor

(iv) One nominee of the Government

(v) One educationist of repute to be nominated by the Government

(vi) One academician to be nominated by the Visitor.

**8.2 Term of the Governing Body**

a. The members of the Governing Body shall have a term of 3 years.

b. If in the opinion of the Chancellor, a member of the Governing Body acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, with approval of the nominating authority, ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

**8.3 Disqualifications of the Members of the Governing Body**

The members of the Governing Body shall cease to members under the following circumstances:

(i) If the individual member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

(ii) If in the opinion of the Chancellor, a member of the Governing Body acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, with approval of the nominating authority, ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

**8.4 Powers of the Governing Body**

a. The Governing Body shall have the following powers:

i. To appoint Auditors of the University.

ii. To oversee the performance and review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the Act, Rules, Statutes or Ordinances;

iii. To approve the annual report and Accounts of the University;

iv. To lay down policies to be followed by the University;

v. To take decision about the voluntary liquidation of the University.

vi. To delegate such powers as it may deem fit to the Board of Management and other authorities or officers of the University.

b. The Governing Body shall perform such other functions as it may deem necessary for proper functioning and administration of the University.

**8.5 Reserve Powers of Governing Body**

a In case of any deadlock in the Board and operations of the University cannot be conducted in the normal course, reserve powers are vested with Governing Body to do all necessary things including superceding the Board and forming a new Board to facilitate smooth functioning of the University.

b The reserve powers of the Governing Body shall be exercised only when there is a written report sent by the Registrar to the Chancellor or the Vice-Chancellor about the deadlock in the Board, and when the operations of the University cannot be conducted in the normal course.

c Upon receipt of such a written report, the Chancellor or the Vice-Chancellor shall direct the Registrar to convene a special meeting of the Board within 15 days, for restoration of normalcy in operations. In the event of Registrar not convening such a special meeting, the Chancellor shall convene such a meeting.

d The decisions taken by the Governing Body and implemented by the officers under this clause shall be final and binding on all the Members of the Board and on all the Members of the Governing Body.

**8.6 Meetings of the Governing Body**

a The Governing Body shall meet at least twice in a calendar year, on any working day, at the headquarters of the university or any other location as may be agreed by majority of the members.

b The Chancellor shall be the Chairman of the Governing Body and shall preside over the meetings of the Governing Body. In absence of the Chancellor, the Vice-chancellor shall preside over the meeting.

c A notice of 21 days shall be given to the members stating the agenda for the meeting. A notice less than 21 days may be considered sufficient if majority of the members agree to such a shorter notice.

d The quorum of the meeting shall be 3 members present in person.

e Each member of the Governing Body including the presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be adopted by simple majority. In case of a tie, the presiding officer shall have a casting vote.

f The presiding officer of the meeting shall cause the minutes of the meeting to be recorded and circulated to the members within a period of one month from the date of such meeting.

**8.7 Extraordinary meeting of the Governing Body**

a In the event of exigency, the Chancellor or the Vice-Chancellor with the concurrence of the Chancellor may call for the extraordinary general meeting of the Governing Body.

b The Sponsor, may, in the event of exigency and / or in the interest of the administration of university, request the Chancellor, or in his absence, the Vice-chancellor either to call for an extraordinary meeting or circulate the resolution among the members of the Governing Body.

c The Chancellor or the Vice-Chancellor with the concurrence of the Chancellor, may, under exigencies, obtain the consent of the Governing Body by circulating appropriate resolution among its members, and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Governing Body.

**9.0 The Board of Management**

The Board of Management shall be the principal executive body of the University.

**9.1 Constitution of the Board of Management**

a. Following members shall constitute the Board:

(i) The Vice-chancellor.

(ii) The Registrar.

(iii) One representative to be nominated by the State Government.

(iv) Senior most Professor of the University to be nominated by the Chancellor.

(v) Two representatives to be nominated by the Sponsor.

b. The Vice- Chancellor shall be the Chairman of the Board and the Registrar shall be the Member-Secretary.

c. The Vice-chancellor shall preside over the meetings of the Board and in the absence of the Vice-Chancellor, the Registrar shall conduct the proceedings of the meeting.

d. The tenure of the members of Board of Management shall be three years, except in the case of Ex-officio members.

**9.2 Disqualifications of the Members of the Board**

The members of the Board of Management shall cease to members under the following circumstances:

(iii) If the individual member is convicted in a court of law for any criminal act including acts of moral turpitude or for any other reason and no stay order has been passed by the higher court against conviction.

(iv) If in the opinion of the Chancellor, a member of the Board acts in a way detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, with approval of the nominating authority, ask such member to relinquish his office from such date as may be specified.

**9.3 Meetings of the Board**

a. The Board of the Management shall meet as often as necessary, and at least once in three calendar months.

b. The meetings shall be called by the Registrar.

c. A notice of 7 days shall be given for the meeting, provided that an emergency meeting may be convened, at the discretion of the Vice Chancellor, at a short notice.

d. The quorum of the meeting shall be 3 members present in person.

e. Each member of the Board including the Chairman/ presiding officer shall have one vote and decisions at the meeting shall be taken by simple majority. In case of a tie, the presiding officer shall exercise a casting vote.

f. The Registrar shall cause recording of minutes of the meeting, with the approval of the Vice Chancellor and circulate them to the members concerned within a period of one month from the date of conducting of the meeting.

g. The Vice-Chancellor may, under exigencies, obtain the consent of the Board by circulating appropriate resolution among its members, and any resolution so circulated and approved by a simple majority shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at the meeting of the Board

9.4 **Powers of Board of Management**

The Board of Management shall have the powers to take all the necessary decisions for smooth and efficient functioning of the University. The powers shall, interalia, include; but not limited to, the following:

A. Financial matters:

a. To consider the budget as recommended by the Finance Committee and to approve the same with or without modifications

b. To manage and administer the revenues and properties of the University and to conclude all administrative affairs of the University not otherwise specifically provided for.

c. To manage and regulate the finance, accounts, investments, property and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agent or agents as it may deem fit.

d. To open account or accounts of the University with any one or more scheduled banks and to lay-down the procedure for operating the same.

e. To draw, accept, make, endorse, discount and negotiate securities of the Government, promissory notes, bills and exchange, cheques or other negotiable instruments.

f. To issue appeals for funds for carrying out the objects of the University.

g. To receive grants, donations, contributions, gifts, prizes scholarships, fees and other moneys; and to give grants and donations, to award prizes, scholarships etc.

h. To purchase, take on lease or accept as gift or otherwise any land or buildings or works which may be necessary or convenient for the purposes of the University, and, on such terms and conditions as it may deem fit and proper and to construct or alter and maintain any such buildings or works.

i. To acquire intellectual property rights, copy rights, trade marks and the like from any institution or organization, on such terms and conditions as the Board may determine, and pay such compensation for the acquisition as may be just and equitable.

j. To transfer or accept transfers of any moveable property on behalf of the University.

k. To execute in consultation with the Holding Trustees (if any) / Sponsor, conveyance, transfer, re-conveyances, mortgages, leases, bonds. licenses and agreements in respect of property, moveable or immovable belonging to the University or to be acquired for the purposes of the University.

l. To appoint, in order to execute an instrument or transact any business of the University, any person as attorney of the University with such powers as it may deem fit.

m. To invest the funds of the University or money entrusted to the University, in such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment.

n. In consultation with the Holding Trustees(if any) / Sponsor, to raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations or securities by providing properties and assets of the University as security, or borrow money without any securities, and upon such terms and conditions as it may think fit, and to pay out of the funds of the University, all expenses, incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed.

o. To maintain and operate the General Fund as stipulated in Section 20.0 of these First Statutes;

p. To maintain proper accounts and other relevant records and prepare Annual Statements of Accounts including the Balance-sheet for every previous financial year, in such form as may be prescribed by the Regulations and submit the same to the Governing Body for their approval.

B. Appointments:

a. To create teaching and academic posts and to decide on the number, qualifications and cadres thereof, and to determine the emoluments of such posts.

b. To appoint Directors, Principals, Deans, Professors, Associate Professors and other senior academic and operational staff, as may be necessary.

c. To lay down rules with respect to emoluments and duties for the various academic and non-academic staff recruited by the University.

d. To lay down rules for appointment of Visiting Fellows and Visiting Professors and their emoluments.

e. To appoint internal auditors to undertake audit of the various functions of the University.

C. Academic Matters:

a. To generally lay down, in consultation with the Academic Council, the academic policies, education and teaching standards and policies relating to student admission, examinations and award of degrees, diplomas and certificates and other academic awards or distinctions.

b. To establish, on the advice of the Academic Council, Divisions and Departments for the academic work and functions of the University and to allocate areas of Study, Teaching and Research to them.

c. To lay down policy in relation to fees and other charges payable by the students of the University.

d. To institute Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes in accordance with the Regulations.

e. To lay down rules regarding the emoluments and traveling and other allowances of examiners, moderators, tabulators and such other personnel appointed for examinations, in consultation with the Academic Council and the Finance Committee.

D. Student Matters and Discipline:

a. To regulate and enforce discipline among the employees and the students of the University and to take appropriate disciplinary action, wherever necessary.

b. To entertain and adjudicate upon any grievance of the employees and students of the University; and to set up Committees for attending to such grievances.

c. To establish and regulate the maintenance of hostels for the students of the University and recognize hostels established by outside parties, on the basis of the recommendations of a committee established for the purpose.

E. Administrative and legal matters:

a. To appro[illegible]e contracts and works.

b. To create administrative. ministerial and other necessary posts and fix compensation for persons recruited to such posts.

c. To grant leave of absence to the Vice-Chancellor or any other officer of the University and to make necessary arrangements to carry out the functions of such officers proceeding on leave during their absence.

d. To conduct inspections and enquires, in various department, centers, institutions and affiliate colleges of the University and initiate corrective action wherever needed.

E. Formation of Sub-Committees:

The Board of Management may form Sub-Committees and / or Ad-Hoc Committees for discharging any of the functions of the Board, by clearly specifying their scope, jurisdiction, authority, powers and functions.

**9.5 Delegation of powers**

The Board of Management may by a resolution, delegate to the Vice-Chancellor, Registrar, Standing Committee or the Ad-hoc Committee, such of its powers as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by the Vice-chancellor or the Standing Committee or the Ad-hoc Committee, or any of their Officers to whom such powers are delegated, shall be reported at the next meeting of the Board of Management.

**10.0 The Academic Council**

a. The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Regulations and shall have the control over and be responsible for the maintenance of standards of education, teaching and training, inter-departmental co-ordination, research, examinations and tests within the University.

**10.1 Constitution of the Academic Council**

a The Academic Council shall consist of the following members:

i. The Vice-Chancellor.

ii. The Registrar.

iii. Five Heads of various Institutions under the University to be nominated by the Chancellor.

iv. Five faculty members designated as professors and drawing pay of professors as prescribed by the UGC to be nominated by the Chancellor.

v. Five outside experts nominated by 'the Chancellor.

b The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Academic Council.

c The term of members of the Academic Council shall be three years, except in the case of the employees of the University who are members of the Academic Council. The term of such members who are employees ends immediately after their relinquishing their office at the University.

d Subject to the provisions of this Act, Statutes and the Regulations the Academic Council shall have the power to control, regulate and maintain the standards of education, instruction and examinations of the University and shall exercise such other powers and functions as may be conferred or imposed upon it by this Act, Statutes or the Board.

e. The Vice-Chancellor may invite such other persons, as he may deem fit, to attend the meetings of the Academic Council from time to time. However, such persons invited shall not be eligible to vote on any of the resolutions of the Academic Council.

**10.2 Disqualification of the Members of the Academic Council**

a Where a person has become a member of the Academic Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when the ceases to hold that office or appointment.

b A member of the Academic Council shall cease to be a member in the following circumstances:

i. If the Member resigns from the Academic Council.

ii. If the Member becomes mentally unsound.

iii. If the Member had been convicted of a criminal offence involving moral turpitude or any other reason, and a higher court has not stayed such conviction.

iv. If the Member fails to attend three consecutive meetings of the Academic Council, without leave of the Chairman.

**10.3 Meetings of the Academic Council**

a The Academic Council shall meet as often as may be necessary.

b One third of the total members of the Academic Council shall constitute the quorum of the meeting of the Academic Council.

c Resolutions of the Academic Council may be passed through circulation of such Resolutions among all the members, except in cases where such Resolutions are required to be passed at a meeting convened. The Resolution so circulated and approved by a simple majority shall be effective and binding as if such Resolution had been passed in the meeting of the Academic Council, provided that at least one half of the total number of the members of the Academic Council have recorded their views on the Resolution.

**10.4 Functions and Powers of the Academic Council**

Subject to the provisions of the Act, Statutes and the Ordinances, the powers of the Academic Council shall include, *interalia*, the following:

a. To report and act on any matter referred or delegated to it by the Board.

b. To formulate different courses and programs to be imparted to the students of the University.

c. To lay down the curriculum and frame syllabus for any of the courses and programs offered by the University, and publish text books and other instruction material for the same.

d. To make recommendations to the Board, with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments and the duties attached thereto;

e. To formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Board as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another.

f. To make arrangements through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University.

g. To promote research activities and programs, and to ask for, from time to time, reports on such research activities and programs;

h. To consider proposals submitted by the faculties relating to instruction, teaching facilities, etc;.

i. To appoint committees for admission of students to the University,

j. To recognize diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University on reciprocal basis;

k. To approve conferment of degrees, honours, diplomas, licenses, titles and marks of honour on the basis of the results declared;

l. To make guidelines for the award of fellowships, stipends, scholarships, medals and prizes, etc., and empower the Vice-Chancellor or any other officer of the University to approve the eligible candidates for such awards.

m. To prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of the Act and / or the regulations.

n. To make recommendations to the Board of Management on:

(i) Measures for improving of standards of teaching, training and research and examinations.

(ii) Institution of Fellowships, Exchange Programs, Scholarships, Medals, Prizes etc.

(iii) Regulations covering the academic functioning of the Institute, discipline, residence, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free ships, concessions, attendance etc and submit the same to the Board of Management for approval.

o. To suggest measures for departmental co-ordination.

p. To appoint committees, consisting of such members as the Academic Council may deem fit, to deal with any of the matters ordinarily dealt with by the Academic Council.

**11.0 Examination Committee**

1. The Vice Chancellor shall constitute Examinations Committee with respect to each faculty, for the purpose of recommending suitable persons for appointment as examiners for various examinations and for suggesting evaluation methods for each subject of the faculty.

2. The Examinations Committee shall consist of :
   - i. The Dean of the Faculty, Chairman
   - ii. Professor of the subject.
   - iii. One expert in the subject nominated by the Chancellor.

3. The examination committee shall recommend a panel of examiners for each subject of the courses of study to the Vice Chancellor.

4. The Vice Chancellor shall ordinarily appoint examiners from the panel recommended by the examinations committee, provided that with the approval of the Chancellor he may appoint examiners outside the panel, if he deems fit and necessary.

**12.0 Results Committee**

a. The Vice Chancellor shall constitute a Results Committee to approve the results of various examinations before they are declared.

b. The Results Committee shall consist of:
   - i. Dean of the faculty concerned.
   - ii. One professor of the subjects assigned to the faculty.
   - iii. One expert nominated by the Chancellor.
   - iv. The Registrar.

c. If in the opinion of the Results Committee the result of any examination is not properly balanced or evaluation of any paper is not properly balanced, the Results Committee may recommend action to be taken by the Vice Chancellor.

**13.0 The Finance Committee and its constitution**

a The Governing Body may appoint Finance Committee.

b The Finance Committee shall consist of the following members namely;
   - i. The Vice-chancellor
   - ii. The Registrar
   - iii. The Chief Finance and Accounts Officer
   - iv. Two nominees of the Sponsor who are members of the Governing Body, to be nominated by the Chancellor.

c The Vice-chancellor shall be the Chairman of the Committee and in his absence the Registrar shall preside over the meetings of the committee.

**13.1 Meetings of the Finance Committee**

a The committee shall meet as often as necessary.

b The quorum of the meetings shall be one third of the members of the committee

c The Registrar shall call the meeting of the Finance Committee with the approval of the Vice Chancellor.

d A notice of 7 days shall be given to its members stating the agenda, time and place of the meeting, provided that an emergency meeting can be called by the Vice Chancellor at a shorter notice.

e The Registrar shall cause recording of the minutes and resolutions of the meeting and circulate the same with the approval of the Vice Chancellor.

**13.2 Powers and Functions of the Finance Committee**

a To make recommendation on all financial matters to the Board.

b To consider all proposals for capital expenditure and to make recommendations to the Board.

c To examine the annual accounts of the University and advise the Board.

d To examine the annual budget estimate and advise the Board thereon

e To review the financial position of the University from time to time and recommend any action to be taken to the Board.

f To review the internal controls and act on the comments of the internal auditors.

g To make recommendations to the Board on all proposals involving the raising of funds, receipts and expenditure.

h To determine and fix the fee payable by the students of the University and lay down the procedure therefor; and to fix the basis for charging consultancy and other fee to be charged by the University.

i To generally perform and act on any of the activities that may be delegated by the Vice-Chancellor, or the Board or the Governing Body.

**14.0 Selection Committee**

a. The Board may appoint a selection committee to recommend names of the persons to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and such other academic posts as may be prescribed by the Board of Management.

b. The selection committee so appointed shall consist of:

i. Three experts in the relevant disciplines nominated by the Chancellor

ii. One Nominee of the Board of Management not connected with the University and not below the rank of a professor.

iii. Dean of the faculty.

**15.0 Constitution of Standing Committees and Ad-hoc committees**

a. The Governing Body and/or the Board of Management may, at the appropriate time, by a resolution in a duly conducted meeting, and or in accordance with the directions of the Chancellor, appoint standing committees or ad hoc committees, and / or enquiry committees by defining --

i. The purpose of appointment

ii. The constitution

iii. The tenure of the committee

iv. The financial budget

v. The procedure to be adopted

vi. The rights and obligations of the committee

vii. The remuneration payable to the members of the committee

viii. The facilities to be acquired and

ix. Other matters relevant or incidental to complete the purpose for which it is appointed,

b. The committees so appointed shall exercise their powers and functions within the delegated authority. Neither the University nor the Governing Body, nor the Board of Management shall be accountable for the authority or powers used outside the scope of delegation by such committees.

c. Such committees shall be automatically dissolved on completion of their tenure or after completion of the tasks assigned to them by the authority appointing them, unless extension in the tenure is granted by the said authority.

**16.0 Advisory Committees**

a. The Board may, with the concurrence of the Chancellor, appoint an Advisory Committee consisting of five members for the purpose of providing advice to the Board in matters relating to the conduct of various affairs of the University.

b The Board may direct the Academic Council, Finance Committee and / or any other committee set up under the Act or these Statutes, to appoint and / or follow the recommendations of the Advisory Board.

c The Board may define the functions, and powers while establishing such committees.

**17.0 Service Conditions for Faculty members, Officers and other Employees**

a. The Board shall formulate the terms and conditions of appointment and of service of faculty members, officers and employees.

b. The Registrar shall issue the appointment letters to faculty members, officers and employees in accordance with the policies and procedures as formulated by the Board.

**18.0 Budgets**

a. The Chief Finance and Accounts officer, with the approval of the Finance Committee, based on the proposed budgets received from different departments, divisions, colleges, institutes of the University, shall prepare an annual budget for the forthcoming financial year, and submit at least two months before the beginning of financial year to the Board for the purpose of approving the same. The Board, upon the merits may suggest modifications, alterations or additions or approve the same with or without modifications and such approved budget will be the annual budget of the University for the year.

b. No expenditure other than that provided in the budget shall be incurred by the departments, divisions, colleges, and institutes of university without the approval of the Finance Committee.

c. The Finance Committee may consider any revision of the Budget, based on the recommendation of the Chief Finance and Accounts Officer and on merits, and such revisions shall be placed for ratification of the Board, at a subsequent meeting of the Board.

**19.0 Accounts and Audit**

a The accounting year of the University shall be from 1st April of a year to 31st March of the following year.

b The accounts of the various divisions, departments, institutions and campuses of the University shall be consolidated by the Chief Finance and Accounts Officer and he shall make out the final annual accounts, consisting of the Income and Expenditure Account and the Balance Sheet of the University and place the same before the Finance Committee for their comments. The appropriations of excess income over expenditure or the absorption of excess of expenditure over the income shall be decided by the Finance

Committee. The accounts will thereafter be adopted by the Board, after which they will be audited by the Auditors appointed by the Governing Body.

c All the assets of the University shall be maintained in the name of the university and shall be used for the settlement of liabilities at the time of liquidation or closure of university under sections 33 and 34 of the Act.

d The accounts of the University shall be open to examination by the Chancellor, Vice-Chancellor, Registrar, Auditor of the University and any other person authorised by the Governing Body or the Sponsor for the purpose.

e Every balance sheet and income and expenditure account of the University shall comply with the relevant accounting standards as may be prescribed by the Government of India in consultation with the National Advisory Committee on Accounting Standards.

f. The Vice-chancellor shall place such audited financial statements before the Governing Body, along with the report of the Auditors for information.

g. The Registrar, thereafter along with the annual report of the University, shall submit such financial statements to the Visitor and the Government as provided under section 30 of the Act.

20.0 Arbitration in case of disputes

a. The Vice Chancellor shall be responsible for resolution of disputes and grievances between the teachers, officers and other employees and the students of the University.

b. The Vice-Chancellor may delegate the responsibility for arbitration to the Registrar or the Deans of the Faculties as he may deem fit.

c. Any person who is aggrieved of the decision of the Vice Chancellor may appeal to the Chancellor within 15 days of communication of the decision by the Vice Chancellor.

d. Where it is found necessary the Chancellor may appoint an Arbitration Committee to arbitrate such disputes and grievances, with such constitution and such powers as he may deem fit.

e. The procedures for arbitration of disputes shall be laid down by the Board.

21.0 Regulations and Manuals

a. Save as otherwise provided in the Act and the Statutes, the Board may make Regulations, as empowered under Section 37 of the Act, to conduct the business of the University and attain the objectives

for it is established. The Regulations may, interailia, relate to the following:

iv. Number of seats in different programs of the University, not otherwise prescribed for by any other statutory bodies authorized for the purpose.

v. Reservation of seats in different programs of the University not otherwise prescribed for by any other statutory bodies authorized for the purpose.

vi. Admission of students.

vii. Fee and other charges payable by the students.

viii. Examinations and student assessment.

ix. Award of scholarships, bursaries, fee waivers, etc to students.

x. Discipline of students and staff.

xi. Resolution of disputes among students and staff and procedure for arbitration.

xii. Conferment of Honorary degrees to distinguished persons.

xiii. Finance and administration of the University.

b The Board may appoint an ad-hoc committee to draft the Regulations and to prepare manuals for different departments / functions of the University.

c The committee appointed above, shall have such members as nominated by the Board and perform all the functions as required under the order of appointment/constitution.

d On satisfying themselves on the Regulations made out by the committee appointed for the purpose, the Board may adopt them for the University.

e Each and every authority and officer, teaching and non- teaching staff, members of the committees and the students are bound to adhere to the provisions and procedures laid down in the manual of instructions drafted for the purpose.

f The Board shall have right to alter, amend, frame new rules and regulations which are not inconsistent with the provisions of the Act for the purpose of conducting the activities of the university for which it is established.

**22.0 Subsequent Statutes**

The Governing Body shall make, amend, alter, modify these First Statutes, and the Ordinances as required for the administration of the University and submit the same to the Government for approval.

**23.0 Ordinances**

The Vice Chancellor of the University shall cause the Ordinances of the University to be made as per the provisions of Section 27 of the Act, and shall submit the same to the Government for their approval. He shall carry out the necessary changes in the Ordinances, as suggested by the Government, and shall table the Ordinances after their due approval by the Government, in the next meeting of the Governing Body. The Vice Chancellor shall follow similar procedure while making any modifications to the Ordinances, or for introducing new Ordinances.

**24.0 University to be open to all Classes, Castes and, Creed.**

a. The University shall be open to all persons of either sex and of every caste, creed, religion, race, or class or place of domicile or Nationality and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a Teacher of the University or to hold any other office therein or to be admitted as a student in the University or to graduate there at or to enjoy or exercise any privilege thereof;

b. Notwithstanding any thing contained in clause (a) the University shall make special provisions in the Regulations for the employment or profession of educational interests of women, persons with disability or of persons belonging to the weaker sections of the society and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes as may be directed by the State Government from time to time.

**25.0 Interpretation**

a. In the event of conflict of opinion with regard to the interpretation of the Statute, Ordinances and Regulations, the provisions of the Act shall prevail.

b. The decision of the Governing Body on interpretation shall be final and bending.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 117/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | गोड़बोरदी प.ह.नं. 9 | 1.690 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | टर्न की पद्धति से कुरदा वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 118/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | हालाहुली प.ह.नं. 10 | 0.975 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | टर्न की पद्धति से कुरदा वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 119/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूवी के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | हालाहुली प.ह.नं. 10 | 2.483 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | टर्न की पद्धति से कुरदा वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 120/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | हालाहुली प.ह.नं. 10 | 0.331 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 4, डभरा. | टर्न की पद्धति से कुरदा वितरक नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 121/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | भेलवाडीह प.ह.नं. 06 | 3.853 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 122/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | तिऊर प.ह.नं. 08 | 1.222 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 123/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | सरवानी प.ह.नं. 08 | 1.966 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 124/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | खरसिया प.ह.नं. 11 | 6.706 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 125/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | अंजोरीपाली प.ह.नं. 11 | 4.085 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 126/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | महुआपाली प.ह.नं. 11 | 4.946 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 127/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | गिधा प.ह.नं. 12 | 1.930 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 128/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | रानीसागर प.ह.नं. 13 | 0.551 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 129/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | कुनकुनी<br>प.ह.नं. 13 | 2.076 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 130/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | खैरपाली<br>प.ह.नं. 15 | 0.369 | कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया. | टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुबोध कुमार सिंह**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2003

क्रमांक 697/अ.वि.अ./भू-अर्जन/43-अ/82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुन्द | महासमुन्द | शेर प.ह.नं. 131 | 3.18 | कार्यपालन यंत्री, कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द, (छ. ग.). | भलेसर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत फीडर नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मनिन्दर कौर द्विवेदी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2002-2003/4682.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-परसापाली,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.862 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 64/12 | 0.105 |
| 64/16 | 0.089 |
| 64/13 | 0.036 |
| 65/1 | 0.146 |
| 66/2 | 0.077 |
| 67/3 | 0.057 |
| 67/4 | 0.008 |
| 67/8 | 0.073 |
| 67/5 | 0.020 |
| 67/7 | 0.077 |
| 67/23 | 0.004 |
| 68/2 | 0.008 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 68/5 | 0.162 |
| योग 13 | 0.862 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जुलाई 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2002-2003/4683.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-ढुसेकेला,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.189 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 457 | 0.061 |
| 460/2 | 0.089 |
| 430/2 | 0.081 |
| 420/1 ख | 0.089 |
| 416/3 | 0.032 |
| 410 | 0.028 |
| 409/2 | 0.138 |
| 586/1, 2, 7, 586/8 | 0.389 |
| 598/2 | 0.024 |
| 607/2 | 0.162 |
| 635/1 | 0.012 |
| 456 | 0.061 |
| 460/1 | 0.028 |
| 419 | 0.012 |
| 416/1 | 0.036 |
| 416/4 | 0.028 |
| 606 | 0.113 |
| 585/1, 585/3, 585/5, 585/6 | 0.113 |
| 605/2 | 0.008 |
| 617/1 | 0.008 |
| 657/1, 658/1 | 0.077 |
| 602/1 | 0.028 |
| 464/2 | 0.049 |
| 420/1 क, 420/2 | 0.130 |
| 430/1 | 0.113 |
| 414/2 | 0.117 |
| 639 | 0.093 |
| 584 | 0.121 |
| 587/1 | 0.190 |
| 592 | 0.049 |
| 596 | 0.032 |
| 601 | 0.162 |
| 638/1 च | 0.040 |
| 464/1 | 0.077 |
| 458 | 0.040 |
| 462/2, 463 | 0.097 |
| 417 | 0.032 |
| 436/1 | 0.073 |
| 413/2 | 0.093 |
| 409/3 | 0.105 |
| 409/1 | 0.093 |
| 589/3 | 0.267 |
| 637/2 | 0.061 |
| 598/1 | 0.186 |
| 607/4 | 0.061 |
| 635/4 | 0.206 |
| 461 | 0.085 |
| योग 47 | 4.189 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**